

China by France (CA)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no Not necessary. Shri Kanwarlal Gupta has already explained what he has said.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vajpayee, being a bachelor, feels like that.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE)—rose

SHRI A. BALA PAJANOR: I know, you are also a bachelor. Mr. Kamath, a senior member, is a bachelor; he is not here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to say anything?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): Mr. Vajpayee should reconsider his position now.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I would like to take the Leader of the Opposition seriously.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am told that in the confusion that was going on, one paper has not been laid—Item No. 4; Shri Shanti Bhushan.

I did attend the public meeting, but I did not say that the maximum punishment should be given. In fact, I said in so many words that the quantum of punishment is to be decided by Parliament, and not even by the Janata Party. When certain slogans were raised—those slogans were highly objectionable—I admonished those who were raising them, and they kept quiet. Let him go through the proceedings of the meeting. I welcome his assurance that they are opposed to violence. All parties have to exert their influence that there is no outbreak of violence in any form or in any shape because violence and democracy cannot go together.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANAVATE): Sir, on behalf of Shri Shanti Bhushan, I have already laid on the Table the paper mentioned against his name.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all. We now take up the Calling Attention; Shri Brij Bhushan Tiwari.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling Attention; Shri Brij Bhushan Tiwari.

12.12 hrs.

#### CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED AGREEMENT BETWEEN CHINA AND FRANCE AND SUPPLY OF NUCLEAR PLANT AND TECHNOLOGY TO CHINA BY FRANCE UNDER AUTHORISATION OF USA

SHRI K. GOPOL (Karur): On behalf of the House, I congratulate Mr. Saugata Roy on his marriage.

श्री बृज भूषण तिवारी (खलीलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान एक बहुत ही लोक महत्व के विषय की ओर दिखाना चाहता हूँ और प्रस्तुत करना हूँ कि वह उस पर सदन में बयान दे :—

MR. DEPUTY-SPEAKER: We congratulate him.

“संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार से फ्रान्स द्वारा चीन को परमाणु संयंत्र और प्रौद्योगिकी की सप्लाय के लिए चीन और फ्रान्स के बीच समझौते के समाचार।”

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): I think they can join in this. We should have unanimity at least in this respect.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): As the House is aware, press reports have recently appeared stating that France and China have signed an economic agreement in Peking on December 4, 1978, regarding trade between the two countries

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री सीतल राय की शाजारी बरतम ही गई इसके लिये हर्ने अफसोस है।

SHRI A. BALA PAJANOR: He is saying it as a bachelor.

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

over the next seven years. This agreement is reported to include a provision regarding the sale of nuclear power reactors to China by a French firm.

It has also been stated that the nuclear power reactors in question are based on technology originating in the U. S. A. While Government have seen newspapers reports that it is likely that US Government would give their clearance, which would be necessary for their export to China by France, it is understood that the question of their clearance is still under the consideration of the US Government.

Government do not yet have confirmed details and information on the scope and conditions of the reported sale of nuclear power equipment to China. In the absence of these, it is not possible to comment on the precise implications of this transfer of technology which, further, is the immediate concern of the three parties involved. However, I would like to reiterate Government's well-known views on the peaceful utilisation of nuclear energy and the necessity to ensure that any safeguards that may be eventually applied in the matter of the transfer of nuclear technology should be uniform and non-discriminatory covering all activities applicable to nuclear and non-nuclear weapon States.

श्री ब्रज भूषण तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बयान विदेश मंत्री ने सदन में दिया है, वह काफी नहीं है क्योंकि जितना सरल इस समझौते को हम समझ रहे हैं, उतना सरल यह नहीं है। यह समझौता 4 दिसम्बर को हुआ जिसमें केवल प्राथमिक पहलू ही संबन्धित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा का मवाल भी सम्बन्धित है। इसके बारे में सरकार के द्वारा यह बयान दिया जाना कि समाचार पत्रों के जरिये मुझे यह जानकारी मिली है, सचमुच में यह चिन्ताजनक बात है। इसके अमट्टन करना चाहिये था, फ्रांस के एम्बेसेडर यहां पर हैं और हमारे एम्बेसेडर फ्रांस में हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे साधन थे, उनके जरिये हमें इन सारे तथ्यों की जानकारी करनी चाहिये थी।

यह समझौता 4 दिसम्बर को हुआ, ऐसा नहीं है कि अचानक चीन के रुख में या अमरीका या पश्चिमी देशों के रुख में परिवर्तन आ गया क्योंकि लगातार चीन से और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेशन्स नार्मलाइज होते रहे हैं और आज जो यह पुरा बककर है, यह पुरा हो

जाता है जब ताइवान को भी अमरीका ने डीरिक्नाइज कर दिया और पूरी तरह से चीन को समर्थन दिया। इसके लिये 1975 में पीटसबर्ग ने कहा था—

In 1975 Michael Pittsburg strongly argued for close military cooperation between the United States and China.

और इसी के साथ ही साथ अभी ब्रेजहनस्की ने पीकिंग में कहा है कि

"A secure and strong China is in America's interest."

इसी के साथ साथ अमरीका ने अपने तमाम एलाइज को यह अनुमति दी है कि वह चीन की आणविक शक्ति को बढ़ाने के लिये, उसकी वेपन पावर्स को बढ़ाने के लिये आधुनिक सुविधाएं दे सकते हैं, पैसा और मशीनरी दे सकते हैं।

इसी सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण सूचना है, मैं चाहूंगा कि सरकार उम सम्बन्ध में भी अपनी सफाई दे क्योंकि मिराज एफ-1 को वैसे ही फ्रांस ने भी इन्कार किया, परन्तु यह जानकारी मिल रही है कि उसकी एक फेक्टरी पाकिस्तान में खुलने जा रही है और चीन बजाय फ्रांस से सीधा समझौता करने के पाकिस्तान के मारफत ऐसे लड़ाकू विमान खरीद सकता है या उसको बनाने की तकनीकी अपने यहां ले सकते हैं।

यह सारी चीजें इसलिये भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद बदस्तूर है और अभी कराकोरम की जो सड़क बनाई गई है और उसी के साथ-साथ चीन का जो काश्मीर के बारे में इन्टिकोण है कि वे सैल्फ डिटरमिनेशन के प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को पूरा समर्थन देने का वायदा करते हैं। उसके साथ ही साथ चीन का रुख हमारे नार्दन हिल, जो पूर्वी सीमान्त है वहां पर टाइल्स को ट्रेनिंग देने में पूरा हाथ है। इसके साथ ही साथ उनसे हमारा सीमा विवाद बदस्तूर है। तो यह सारे तथ्य और सन्दर्भ हैं और चीन व अमरीका की मिली हुई साजिश कि यह जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, जो एशियन रीजन है, जो पावर ब्लाक है, शक्ति सन्तुलन हुआ है, उसे डिस्टर्ब किया जाये और ऐसा शक्ति सन्तुलन बनाया जाये ताकि एक तरफ अमरीका द्वारा चीन से रूम को आइसोलेट करना है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के ऊपर बराबर यह खतरा बनाये रखा है। उनकी शर्तों पर हम हमेशा चलते रहे और समझौता करते रहे।

इसके साथ तमाम अमरीकी जो शिक्षा-विद हैं इंटेलिक्चुअल्स हैं, इन्टेलीजेंसिया है, वह भी काफी पैमाने पर भारत में आ रहे हैं। चाइना काबं का इस्तेमाल किया जाय, वह सारी की सारी मशीनरी पर भी अपना दबाव का इस्तेमाल करती है और इसके साथ उन्होंने चीन के साथ सम्बन्धों को ठीक करने के लिये बकासत शुद्ध की है, मैं भी इस पक्ष में हूँ। हमारी सरकार ने—हमारे

प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री ने—घोषणा की है कि हम विवाद को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं। लेकिन हुआ साहब ने कहा है कि भारत कन्फ्रीट प्रॉपोजल्ज लेकर आये कि हम सीमा-विवाद को कैसे हल कर सकते हैं। जब एकेडेमीशन्ज का ऐसा दबाव पड़ रहा है और जो लोग आज वाशिंगटन में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, वे इस कोशिश में हैं कि चीन की ताकत बराबर बढ़ती रहे, निरंकुश रूप से बढ़ती रहे, तो वह खतरा मदा बरकरार रहेगा कि भारत को दबाया जाय, उसको कमजोर बनाया जाय। मैं विदेश मंत्री से साफ तौर पर पूछना चाहता हूँ कि क्या यह न्यूक्लीयर क्लब के मेम्बरों की मजिण का ही एक अंग तो नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर इस लिए दबाव डाला जाय कि उनमें अपने आणविक संयंत्रों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण को स्वीकार नहीं किया है? क्या पाण्ड्याय देशों की यह नीति तो नहीं है कि भारत पर इस लिए भी दबाव डाला जाय कि भारत को चीन के निकट आने के लिए मजबूर किया जाय, ताकि भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों में फर्क आये और हम क्षेत्र में एक दूसरे प्रकार के शक्ति-गुट या पावर-ब्लॉक का निर्माण हों ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सारी स्थिति पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है। हम लगानार इस मामले में पैरिस-स्थित अपने दूतावास के जरिये फ्रांस की सरकार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अनुसार अभी तक राजनैतिक, वित्तीय तथा तकनीकी—पॉनीटिकल, फिनांशल एंड टेकनिकल—डीटेल्ज अन्निम रूप से तय नहीं हुई है, और जब तक ये तय नहीं होंगी, तब तक ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि समझौता हो गया।

इस मामले में अमरीका भी एक पक्ष है, क्योंकि अमरीका के यहां से टेकनालोजी का जाना है। चीन कम्युनिस्ट देश है, और अगर अमरीका द्वारा दी गई टेकनालोजी फ्रांस के माध्यम से चीन पहुंचती है, तो इसके लिए अमरीका की स्वीकृति की जरूरत है। कल भी अमरीकी दूता-वास के साथ इस बारे में बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने क्नीयरेस नहीं दिया है।

माननीय सदस्य ने कुछ और मामले उठाये हैं। मैं समझता हूँ कि वे इससे सीधे सम्बन्धित नहीं हैं। अभी परसों विदेश नीति पर, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर, चर्चा होगी, तो हम इन सारे मामलों पर गहराई से विचार कर सकेंगे।

श्री ज्योत्सना त्पायी (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने दिया है, वह सचमुच मेरे लिए भी आश्चर्यजनक

है, और वह इस लिए कि जो न्यूक्लीयर प्लांट दिया गया है, और जो टेकनालोजी के बारे में बातचीत चल रही है, यह तो निश्चित है कि यह प्लांट व टेकनालोजी चीन को दी जायगी। मंत्री महोदय को भले ही संवेह हों, परन्तु अमरीकी गवर्नमेंट ने चाइना को न्यूक्लीयर प्लांट, अस्त्र-शस्त्र और टेकनालोजी से मारनाइज करने और रूस के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन को खड़ा करने का निश्चय कर लिया है। इसी नीति के अनुसार उसने अपने मित्र देशों को, जिनके पास यह ज्ञान है, जहां जहां, इस प्रकार के न्यूक्लीयर प्लांट हैं, यह ज्ञान और टेकनालोजी पौकिंग को देने की अनुमति देने का निश्चय कर लिया है। अभी चाहे अमल न हो परन्तु यह उन की नीति के अनुसार है। मैं यह कहना चाहूंगा आप से, अमरीका ने हमारे तारापुर प्लांट के लिए एनरिचड यूरेनियम देने के समय और फिर अगला जो हमारा इन्स्टालमेंट है जिस के लिए ऐंशोमेंट हो चुका है, उस ऐंशोमेंट के अनुसार उस को यह एनरिचड यूरेनियम देना है लेकिन वह इसलिए देने को तैयार नहीं है कि हम ने सेफगाइंस स्वीकार नहीं किये और नान-प्रालिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। अमरीका में एक इस प्रकार का लेजिस्लेशन भी पाम हुआ है कि इस प्रकार के देशों को टेकनालोजी और एनरिचड यूरेनियम न दी जाय जब तक वे इस प्रकार के सेफगाइंस स्वीकार न करें, हमें भी वह इस लिए नहीं दे रहे हैं लेकिन चाइना को इस प्रकार की टेकनालोजी देने की बात हो रही है और यह न्यूक्लीयर प्लांट जा रहा है, यह बात डेफिनिट है तो इस प्रकार का जो अंधेबाव अमरीका सरकार कर रही है, यह जो उस की बाहरी और दोमुखी नीति है उस के बारे में क्या सरकार ने अमरीका सरकार से जानकारी प्राप्त की है कि उन की इस प्रकार की दोमुखी नीति क्यों है, एक समान नीति क्यों नहीं है? जहां जहां भी इस प्रकार की टेकनालोजी वह देगे और इस प्रकार का न्यूक्लीयर प्लांट जायेगा वहां इस प्रकार की बात हो सकती है क्योंकि इसमें प्लूटोनियम भी पैदा होता है जिस से ऐंशम बम बनता है। हमारे यहां उस की जानकारी है क्योंकि जो स्पेट फ्यूएल बचेगा उस की रिफ्यूए-लिंग से प्लूटोनियम पैदा होता है जिस से ऐंशम बम बनेगा। इसलिए यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा सरकार से, यह फ्रांस गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, यह सवाल सीधा अमरीका गवर्नमेंट का है। क्या आप ने अमरीकन गवर्नमेंट से बाकायदा उन की इस नीति की चर्चा की है या नहीं की है कि क्या उन की इस संबंध में यूनिफार्म नीति रहेगी या इस प्रकार की दोमुखी नीति रहेगी और वह हम को भी इसी आधार पर देने या नहीं देने ?

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि अमरीका चाइना को समझ बना रहा है, वह बात सही है और उन की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का वह अंग है। ठीक है, इन्धिया के खिलाफ वैश्विक पावर

[श्री शोब प्रकाश त्यागी]

बड़ी कर रहे हैं, हमें इस में आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ आप से कि जो इस प्रकार से चाइना को सक्षम बनाया जा रहा है और चाइना एक और पाकिस्तान की प्राणविक्रम ज्ञान देने का प्रस्ताव कर चुका है, प्राणविक्रम क्षेत्र में जो टेन्गलाजी चाइना के पास है उस में झालरेडी 40 प्लांट एटम बम बनाने के लिए उस के पास हैं, केवल पीसफुल इस्तेमाल एटमिक एनर्जी उत्पन्न करने की टेकनिकल नो हाउ उस के पास नहीं है, इसलिए उस ने अमेरिका की शरण ली है और यह भी उस को मिल जाती है तो एटमिक एनर्जी के और उसके टेकनिकल ज्ञान से वह पूर्ण हो जाता है और यह उस की नीति है, मैं आप से कहना चाहता हूँ कि माऊ का जो डिक्टम है रेस्पेक्ट दि एनीमी टैक्टिकली एंड डेस्पाइज हिम स्ट्रेटेजिकली, यह उस की नीति है, उसी नीति के अनुसार अमेरिका के साथ उस का समझौता चल रहा है, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान को वह इस प्रकार का आफर कर चुका है, दूसरी ओर माकानेड और मिजोरम के विद्रोहियों को वह हमारे खिलाफ सहायता कर रहा है, और अब यह शक्ति वह प्राप्त कर रहा है तो क्या इस प्रकार के समझौते से अन्तरराष्ट्रीय राजनीति पर कोई फर्क या कोई कुप्रभाव पड़ने की कोई संभावना है या नहीं है और दूसरे क्या हमारी डिफेंस पर भी इस का कोई असर पड़ेगा ? इस देश की सुरक्षा पर, इस देश की नीति पर और चाइना और भारत के सम्बन्धों पर भी इस का कुप्रभाव पड़ने की कोई संभावना है या नहीं ? यदि है तो हमारी सुरक्षा के लिए आप ने क्या किया है ? ऐसा कुप्रभाव न पड़े, इस दिशा में आप ने क्या प्रयत्न किया है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यदि अमेरिका फ्रांस के जरिये चीन को ऐसी टेकनोलॉजी देता है जो साधारणतः अमेरिका और देशों को नहीं देता है और अगर देना है तो उन पर यह शर्त लगाता है कि पाने वाले देश के एटमिक रिएक्टर फुल स्कोप सेफ गार्ड्स में आएंगे। तो चीन के सम्बन्ध में कोई भी भेदभाव करना, यह गलत होगा और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चीन के पास एटम बम हैं, अक्टूबर, 1964 में चीन ने पहला अणु बिस्फोट किया था। हथियारों की दिसा में चीन ने काफी प्रगति की है लेकिन इस सवाल पर चर्चा करते समय हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। माइनाइजेशन के लिए अगर चीन अणु शक्ति चाहता है तो देने वाले देश का यह कर्तव्य है, विशेषकर अमेरिका का, कि वह देखे कि कोई भी ऐसी फुल स्कोप सेफगार्ड्स के अन्तर्गत वह रहना चाहिए जैसे कि तारापुर में है जिससे एटमिक इन्फ्लेक्शन का उपयोग ऐसी तत्व या ऐसे युरेनियम से फ्यूटोनियम बनाने में नहीं हो जिस कि इन्वियन्टो के विस्तार के कार्यक्रम को और भी इस दिशा में न सदन को

विश्वास में लेना चाहूँगा। माननीय सदस्यों ने भी सिनेटर फ्रैंक चर्च जो फारेन रिलेशंस कमिटी के चेयरमैन हैं, के एक वक्तव्य को देखा होगा। उनके कुछ वाक्य मैं उद्धृत करना चाहता हूँ :

“There is a real possibility of selling commercial nuclear reactors to the Chinese. Remember that since the Chinese have already developed a full capacity to manufacture nuclear weapons the normal concern that we have about proliferation of such weapons is not present in the Chinese case.”

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हास्यास्पद है। एक ओर तो अमेरिका प्रोलिफरेशन को रोकना चाहता है और दूसरी ओर प्रोलिफरेशन को रोकने सम्बन्धी जितनी भी शर्तें हैं वह ऐसे देशों पर लगाना चाहता है जिन्होंने पहले से ही फैसला किया है कि हम प्राणविक्रम हथियार नहीं बनायेंगे। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक है कि अमेरिका इस सम्बन्ध में दोहरे माप-दण्ड का उपयोग कर रहा है। इस माप-दण्ड का उपयोग नहीं होना चाहिए और भारत उसका विरोध करेगा।

श्री शोब प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या इस प्रकार के समझौते से अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र और भारतवर्ष पर कोई कुप्रभाव पड़ने की संभावना है या नहीं ? यदि है, तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत है। पड़ोस में होने वाली सारी घटनाओं को ध्यान में रखकर हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर निरन्तर विचार करते रहते हैं और जहाँ भी कमी दिखाई देती है उसको पूरा करते हैं।

श्री उपसेन (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन के सामने रखा गया है, माननीय मंत्री जी जब अग्नी जनवरी में चीन जा रहे हैं उसके सन्दर्भ में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं तीन बातों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं 27 नवम्बर के यू एन प्रार्थ के एक समाचार की दो तीन लाइनें पढ़ लेना चाहता हूँ ताकि मंत्री जी और सरकार इनको समझ ले। वह यू एन प्रार्थ की रिपोर्ट है :

“The reported agreement by China to acquire a sophisticated nuclear plant from France and its arms deals with various western

countries have created a serious situation in the sub-continent."

पश्चिमी देशों से चाइना ने हथियार लेने के जो समझौते किए हैं और अमरीका के साथ उन्होंने न्यूक्लियर धातु लेने की बात की है यह बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या वे इस बात को मानते हैं—वे ठीक ठीक बतायें—क्या यह अमरीकी साम्राज्यवादियों की साजिश है कि हिन्दुस्तान को चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर करने के लिए चीन को हम मदद दें ? इस पर आप प्रकाश डालें कि हमारी नीति क्या है ?

दूसरी बात यह है कि चीन के दुभा कुवो फेंग ने पीकिंग में कहा है कि हमने निश्चय किया है कि पश्चिमी देशों से, जहाँ कहीं से भी हो, हम आधुनिकतम हथियार, प्राणविक हथियार मंगायेंगे और उसी योजना के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चीन की सरकार ने फ्रांस से समझौता किया है।

तीसरी बात यह है क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि चाइना ने यूरोपियन एकोनामिक मार्केट से भी मोस्ट माडर्न वीपन खरीदने का एक समझौता किया है ? क्या मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि आधुनिकतम प्राणविक हथियार और दूसरे किस्म की ऐसी प्राणविक भण्डियां अमर साम्राज्यवादी देश यूरोपियन एकोनामिक मार्केट के नेतृत्व में चीन को दे देंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है, और चीन के पास एटम बम है ही तो उस हालत को देखते हुए क्या मंत्री जी अपने यहां डिफेंस मिनिस्टर का, मुरखा की बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे और उसके लिए तैयारी का मुझसे दंगे ?

मेरी यह मान्यता है और मैं दृढ़-निश्चित हूँ कि अमरीका और पश्चिमी देश हिन्दुस्तान को, जो एक जनतन्त्रीय देश है, उस को कमजोर करने के लिये चीन को उभार रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल हम से मुकाबले की बात नहीं है, बल्कि वे साठ करोड़ की धरती पर गलत निगाह लगायें हुए हैं। चूंकि माननीय मंत्री जी चीन जा रहे हैं—रास्ते में प्रबन्धन वाले हवाई अड्डे पर उन से पूछेंगे—चीन कम्बोडिया को उभार कर वियतनाम के साथ जो कर रहा है, उस ने हमारी जमीन को हड़प लिया है, बर्मा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, चारों तरफ हाथ मार रहा है, पाकिस्तान को उभार कर बढ़ा रहा है—चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की दो नीतियां हैं—समाजवादी और साम्राज्यवादी, रूस भी यही करता है और चीन भी यही करता है—उस की कम्युनिज्म की समाजवादी और साम्राज्यवादी नीति को छोड़ दीजिये—लेकिन जो उस की एक्सपान्डिनिस्ट नीति है—उस के बारे में हमारी सरकार क्या सोच रही है ? मंत्री

जी जब उधर जायेंगे तो उस को संयुक्त-विभक्ति लिखनी पड़ेगी—मैं जानना चाहता हूँ कि उस के लिये आप क्या विभाग बनायेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने स्पष्ट किया—इस प्रश्न के दो पहलू हैं—एक चीन के पास प्राणविक हथियार हैं और चीन उन हथियारों का विकास कर रहा है और चीन जो भी स्वीत उपलब्ध हैं उन से अपनी प्रायोगिकी का विस्तार करने में संलग्न है।

दूसरा पहलू—यह है कि अमर अमरीका उस शर्त की प्रत्येकना कर के जो वह हमारे ऊपर लगा रहा है—तारापुर के सम्बन्ध में एन-रिफ्लेक्ट यूरेनियम देने के बारे में—वह शर्त अमर चीन पर नहीं लगाता—यह कह कर कि चीन के पास पहले से ही एटमिक हथियार हैं—इस लिये उस पर शर्त लगाने की जरूरत क्या है ? यह हमारे लिये न केवल चिन्ता का विषय है, बल्कि हमारे लिये अमरता का विषय भी है और हम अपनी भावना अमरीकी सरकार को प्रबन्धित शब्दों में बतला रहे हैं—केवल उन देशों के बारे में "फुल-स्कोप-सेफगार्ड्स" नहीं हो सकते जब के पास हथियार नहीं हैं, उन पर सेफ-गार्ड्स लगाने की जरूरत क्या है—हम ने तो पहले ही एलान कर दिया है . . . . .

श्री कवर लाल मुन्ध (दिल्ली सदर) : आप भी बनाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या अमरीका यह चाहता है ? मैं नहीं समझता कि अमरीका यह चाहता है, मगर जो अमरीका नहीं चाहता है, आज उस से उलटा काम कर रहा है।

श्री बज्र प्रकाश त्रिपाठी : अमर आप रूस से लड़िये तो चाहेंगा।

एक माननीय सदस्य : आप यह भवना व्यक्त कर दीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह भावना व्यक्त नहीं होती है, सरकार की नीति की उद्-घोषणा होती है। संसद में भावना ही व्यक्त की जाती है, हाथापाई नहीं की जाती है। इतने बड़े देश के, इतने शक्तिशाली देश के, जिस देश में इतने प्रबल व्यक्ति हों, उन के प्रवक्ता के रूप में अमर मैं कुछ कहना हूँ—तो वह भाव भावना का प्रकटीकरण नहीं है, वह मन्त्रे भावना की घोषणा है . . . . .

डा० कर्ण सिंह (उज्जयपुर) : भावना के कर्तव्य ऊंचा होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्तव्य का अर्थ जब प्रायेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब उधरन जी ने पूछा कि चीन अमर-अमर अमर के तैयारी कर रहा है,

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पाकिस्तान को भी वह बीच में लाये और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी उल्लेख किया—मैं समझता हूँ ये सारे मामले यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, मगर सीधे इस में से नहीं निकलते हैं और जैसा मैंने कहा है—परसों हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर एक विवाद चर्चा करने वाले हैं, उस में ये सारे मामले उठाये जा सकते हैं।

श्री हार्केश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी प्रश्नों को माननीय मंत्री जी के सामने रखा और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत सी बातों का जवाब दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं भी उनके सामने रखना चाहता हूँ।

जो कुछ भी समझौता हुआ फ्रांस और चीन के बीच और यह अमेरिका की सहमति से समझौता हुआ। क्या इस समझौता से भारत की सुरक्षा और विदेश नीति दोनों पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा? यह न केवल भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर बल्कि दुनिया के अन्दर चीन और अमेरिका के बीच सम्बन्ध कायम होने के बाद पूरी विश्व की राजनीति को आग्राम ही क्या नहीं बदलेंगे?

यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज अमेरिका जो कार्य कर रहा है उस से साफ जाहिर है कि वह दोहरी नीति अपना रहा है। 1954 में जब राष्ट्रपति ब्राइजनहावर ने भारत से कहा था कि भारत को चाहिए कि साम्यवादी देशों के प्रसार को रोकने के लिए भारत हथियार ले तो उस समय भारत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी और आज की राजनीतिक स्थिति क्या है? राष्ट्रपति कार्टर चीन की प्रायुध शस्त्र शक्ति, सामरिक शस्त्र शक्ति और दूसरी शस्त्र शक्ति को बढ़ाने के लिए चीन को मदद देने के स्तर तक उतर आये हैं। इस से साफ जाहिर है कि भारत के प्रति इन लोगों का इरादा साफ नहीं है। वे भारत को कमजोर बनाना चाहते हैं और भारत को ही नहीं, भारत से सम्बन्धित जितने भी राष्ट्र हैं जिन के साथ भारत के अच्छे सम्बन्ध हैं उन को भी कमजोर करना चाहते हैं।

जहाँ तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है, उन्हें मालूम है कि चीन के साथ भी सोवियत संघ के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं और भारत के साथ चीन के सम्बन्ध पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसलिए सोवियत संघ और भारत दोनों को कमजोर करने की दिशा में यह उनकी साजिश है। भारत रूस मैत्री इतिहास की सच्चाइयों एवं वास्तविकता पर आधारित है। हमें रूस के साथ अपने सम्बन्ध निरन्तर कायम रखने और उन्हें उत्तरोत्तर मजबूत बनाते रहने की आवश्यकता है। चीन-अमेरिका सम्बन्ध सोवियत संघ को नीचा दिखाने और भारत की स्थिति को कमजोर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक षडयंत्र प्रतीत होता है।

मान्यवर, इन सच्चाइयों के तहत, मैं सिर्फ बात को माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि

अगर हमारे तारापुर के एटोमिक प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जिस को 1994 तक अमेरिका द्वारा यूरोनियम देने का समझौता हुआ था, उसे आज अमेरिकी राष्ट्रपति स्वीकार करने को क्यों नहीं तैयार हैं? अगर वे स्वीकार भी करते हैं तो उन के देश की जो अन्य संस्थाएँ हैं, जो इसे देती हैं या इसको देने की अनुमति प्रदान करती हैं उन पर वे क्यों नहीं अपना दबाव डाल पा रहे हैं? मेरे पास जो कटिंग है उस में साफ लिखा है—

“The US president, Mr. Jimmy Carter, overruling State Department objections has authorised France to sell American-licensed nuclear reactors to China.”

वे चीन के साथ इस तरह का समझौता कर सकते हैं लेकिन तारापुर पावर प्लांट के लिए यूरोनियम देने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे राष्ट्रपति कार्टर को पत्र लिख कर उन से यह स्पष्ट जानना चाहेंगे कि अमेरिका चीन की परमाणु शक्ति को बढ़ा कर क्या भारत और विश्व शांति के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहता है? क्यों भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ किये गये वायदे को भी पूरा नहीं किया जा रहा है जबकि चीन को हथियारों के मामले में मजबूत करने से भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ मैत्री रखने का इरादा छोड़ चुके हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, तारापुर के सम्बन्ध में अमेरिका के साथ हमारा जो समझौता हुआ है उस समझौता का पालन होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने जो कानून बाद में पारित किया है, उस कानून को उसके बनने से पहले हुए समझौते पर लागू नहीं किया जा सकता। हमें एक किस्त मिल गयी है, दूसरी किस्त मिलेगी, इसकी हम आशा करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रेजिडेंट कार्टर का रुख सहायक है, यह हमें मालूम है। लेकिन वहाँ और भी एजेन्डियाँ हैं जो हम मामले में आग्रणियाँ करती रहती हैं। वह एक लोकतंत्रवादी देश है लेकिन उस सब के बावजूद हमें आशा है कि अमेरिका हमारे साथ किये गये करार का पालन करेगा और अगर नहीं करेगा तो हम तारापुर को चलाने के लिए अन्य स्त्रीतों से इंतजाम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या प्रेसीडेंट कार्टर की चिट्ठी लिखी जयगी? अब प्रेसीडेंट कार्टर और प्रधान मंत्री के बीच में पत्र-व्यवहार चलता रहता है, उसमें अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होती है, द्विपक्षीय मामलों पर भी विचार विनिमय होता है। और मैं समझता हूँ कि जब यह मामला अन्तिम रूप लेगा तो इस मामले को भी उच्च स्तर पर उठाया जा सकता है।

श्री बलबन्त सिंह राम्बालिया (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। नई जनता सरकार की यह भरसक कोशिश रही है कि इसके सम्बन्ध पड़ोसियों के साथ आसतौर पर अच्छे हों। इस देश में राजनीतिक कई वक्ता मोड़ तोड़ किये गये, पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने के लिये यहाँ से ही बहुत सी बातें कही गईं। रूस के खिलाफ प्रचार हमेशा तेज रहता है, इसी तरह चीन

खिलाफ भी। मैं समझता हूँ चीन को हमेशा दुश्मन का कतार में खड़ा रखना यह कोई लियाकत या सूझ की बात नहीं है। चीन भी हमारा दोस्त हो सकता है। हमेशा चीन को दुश्मन कहा जाता और वहाँ छोटी छोटी बातें हॉनें पर उसको बढ़ते विरोध के रूप में हम देश में पेश करना यह कोई ज्यादा फायदेमन्द नहीं रहेगा भविष्य में। यह सरकार क्या चाहती है? फ्रांखर चीन हमेशा से आक्रमणकारी नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हमारे पर आक्रमण किये, मगर अब हम उसके दाम्न बने। आज भाननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय बाजपयी जी को यह श्रेय जाना है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम किये और कितने नजदीक लाये। चीन के लोगों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिये लड़ाई लड़ी, चीन के लोग बड़ादुरी से लड़े। वहाँ के लोगों ने अपने यहाँ से गर्मायेदारी को खत्म किया, और भ्रादमी के हाथ से भ्रादमी की लूट को चीन में खत्म किया गया है। हम चाहते हैं कि उस देश के लोग ईमानदारी से रहें, अच्छाई से रहें, हमारे उनके अच्छे सम्बन्ध रहें। मगर कुछ बातों में बाज दफा जब तीमरी शक्ति अपनी टांग फँसा देती है तो हलाना वैसे नहीं रहते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। भ्रमरीका एक तरफ हमसे दोस्ती की बात करता है मगर भ्रमरीका का यह प्रयास रहता है कि हर जगह दो भ्रादमियों को लड़ाते रहो ताकि बीच में भ्रमरीका का काम चलता रहे। इसलिये हम चाहते हैं कि हथियारों का विस्तार रुके, यह सरकार भी इस पर जोर देती है हथियारों के विस्तार पर रोक लगे और हथियार संसार में न बने। यह सरकार यह भी चाहती है कि दुनिया में भ्रमन हो और एक दूसरे के साथ सहयोग से रहें।

मैं मंत्री जी से दो, तीन बातें पूछना चाहता हूँ। पहली तो यह कि भ्रमरीका में फ्रांस के जरिये जो न्युक्लियर शक्ति वहाँ जा रही है उसके बारे में जो देश में चिन्ता पैदा हो गई है उसके सम्बन्ध में क्या विदेश मंत्री जी जब चीन जायेंगे तो क्या इस विषय को उठावेंगे?

(2) क्या आपने भ्रमरीका के राजदूत को बुला कर भारत सरकार की ओर से अपनी प्रोटेस्ट लात्र किया है?

(3) भविष्य में आप भ्रमरीका के साथ प्रडॉम प्रडॉम के देशों के बारे में जो उनकी जंगी हथियारों की नीति है उसके बारे में कोई डीटेन्ड वार्तालाप करने के लिये डेलीगेशन का यद्दा धाना या यद्दा से डेलीगेशन वद्दा भेजने का आप क्या लखने है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।

13 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं पीकिंग जाऊंगा, तो सभी प्रश्नों पर चर्चा होगी और उनमें यह प्रश्न भी आ सकता है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस मसाले का सम्बन्ध भ्रमरीका से अधिक है, क्योंकि भ्रमरीका ऐसी टेकनालोजी

काय के जरिये चीन को दे रहा है, जिसको धीरों को देते समय बहु फूल-स्कोप सेकुराईज की बात करना है। अणु रैनेटर फ्रेंक र्चब का बक्तव्य सही है, वो चीन के मामलों में वह उम सेकुराईज पर बन देने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि मैं ने अपने पहले उत्तर में कहा है, इस सम्बन्ध में हम भ्रमरीका रूतावास से सम्पर्क बनाये हुए हैं, और अणु रैनेटर को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो फिर कूटनीतिक दृष्टि में जो भी कदम आवश्यक होगा, वह हम उठावेंगे।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के प्रयत्नों में कभी कभी बाधा पैदा करने की कोशिश की जाती है। वह तो भारत और पड़ोसी देशों का कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की बाधाओं को ताक पर रख कर, और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, अपने सम्बन्धों को सुधारे और उनको मजबूत करें। वर्तमान सरकार सभी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अणु हम किसी एक देश के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते हैं, वो वह किसी तीमरे देश की कीमत पर बनाना नहीं चाहते हैं, और इस लिए सम्बन्ध सामान्य बनाने की प्रक्रिया और देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को कमजोर करने के लिए नहीं होगी। उन सम्बन्धों को मजबूत रखने हुए हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों का सामान्य बनाना चाहते हैं।

#### LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the sittings of the House in their Ninth Report have recommended that leave of absence be granted to eight Members, namely, Thakur Girija Nandan Singh, Sarvashri T. A. Pai, Dhar-masinhbhai Patel, Keshavrao Dhondge, K. S. Chavda, Annasaheb Magar, Krishna Chandra Halder and Dr.